

जैविक खेती, कृषि उद्यमिता एवं ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण: उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों का अनुभवजन्य अध्ययन

Rohit Singh

Senior Researcher

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है, जिसमें जैविक खेती सतत कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा किसानों की आय में वृद्धि का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में जैविक खेती, कृषि उद्यमिता एवं ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के मध्य अंतर्संबंधों का अनुभवजन्य अध्ययन करना है। अध्ययन में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति, कृषि उद्यमिता के विकास, किसानों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव, महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता तथा जैविक उत्पादों के विपणन से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में अनुभवजन्य अनुसंधान अभिकल्प अपनाया गया है। उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक निदर्शन विधि द्वारा उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों से 150 किसानों का चयन किया गया। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से तथा द्वितीयक आँकड़ों का संकलन पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों एवं अन्य प्रामाणिक स्रोतों से किया गया। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, माध्य, सहसंबंध (Correlation), काई-वर्ग (Chi-square) तथा प्रतिगमन (Regression) जैसी सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि जैविक खेती किसानों की उत्पादन लागत में कमी, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, यह ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को गति प्रदान करती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रभावी सरकारी योजनाएँ, किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणन तथा संगठित विपणन व्यवस्था जैविक कृषि के विस्तार में सहायक हैं। अध्ययन के आधार पर जैविक प्रमाणन को सरल बनाने, किसानों के कौशल विकास, डिजिटल विपणन, मूल्य संवर्धन तथा कृषि-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

मुख्य शब्द: जैविक खेती, कृषि उद्यमिता, ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश

1. प्रस्तावना

1.1 जैविक खेती का वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य

विश्व स्तर पर जैविक खेती सतत कृषि प्रणाली के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारत जैविक उत्पादकों की संख्या के आधार पर विश्व के अग्रणी देशों में है। भारत में लगभग 44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक प्रबंधन के अंतर्गत है। सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

1.2 उत्तर प्रदेश में जैविक कृषि की स्थिति

उत्तर प्रदेश में जैविक खेती का विस्तार विशेष रूप से बुन्देलखण्ड, तराई एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में हो रहा है। राज्य सरकार प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, जैविक इनपुट तथा विपणन सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है। अनेक किसान समूह एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) जैविक उत्पादन एवं विपणन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

1.3 कृषि उद्यमिता की आवश्यकता

वर्तमान कृषि व्यवस्था में बढ़ती लागत, सीमित आय तथा रोजगार की चुनौतियों के कारण कृषि उद्यमिता की आवश्यकता बढ़ी है। कृषि आधारित उद्योग, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, जैविक उत्पादों का विपणन तथा एग्री-बिजनेस किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं।

1.4 ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण में जैविक खेती की भूमिका

जैविक खेती उत्पादन लागत को कम कर किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक है। यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग, महिला सहभागिता, ग्रामीण रोजगार, खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। जैविक उत्पादों के उच्च बाजार मूल्य से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होता है।

1.5 अध्ययन का औचित्य

वर्तमान समय में सतत कृषि विकास, किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जैविक खेती एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद यहाँ जैविक खेती, कृषि उद्यमिता एवं ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के मध्य अंतर्संबंधों पर अनुभवजन्य शोध अपेक्षाकृत सीमित हैं। राज्य के विभिन्न जनपदों में जैविक खेती को अपनाने की स्थिति, उससे प्राप्त आर्थिक लाभ, रोजगार सृजन, महिला एवं युवा सहभागिता तथा कृषि-आधारित उद्यमिता की संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। यह अध्ययन चयनित जनपदों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर जैविक खेती के सामाजिक, आर्थिक एवं उद्यमशील प्रभावों का विश्लेषण करेगा। साथ ही, किसानों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों, सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता तथा विपणन संबंधी समस्याओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, कृषि उद्यमियों तथा किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और उत्तर प्रदेश में सतत कृषि विकास एवं ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रभावी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे।

1.6 अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. जैविक खेती एवं कृषि उद्यमिता के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।
3. जैविक खेती का ग्रामीण परिवारों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।

1.7 परिकल्पनाएँ

- जैविक खेती किसानों की आय में सकारात्मक वृद्धि करती है।
- कृषि उद्यमिता ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
- जैविक खेती अपनाने वाले किसानों का जीवन स्तर पारंपरिक किसानों की अपेक्षा बेहतर होता है।

2. साहित्य समीक्षा

2.1 जैविक खेती पर पूर्ववर्ती अध्ययन

विलर एवं लेनोर्ड (2021) ने विश्व स्तर पर जैविक कृषि की स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके अध्ययन के अनुसार जैविक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण, मृदा उर्वरता एवं जैव विविधता के संवर्धन में सहायक है, बल्कि किसानों की आय में भी दीर्घकालिक वृद्धि का माध्यम बनती है। अध्ययन में यह पाया गया कि जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग निरंतर बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार एवं अधिक मूल्य

प्राप्त हो रहा है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष दिया कि सरकारों को जैविक प्रमाणन, विपणन, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता को सुदृढ़ कर जैविक कृषि के विस्तार को प्रोत्साहित करना चाहिए।

कुमार एवं सिंह (2022) ने उत्तर भारत के किसानों पर जैविक खेती के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि जैविक खेती अपनाने वाले किसानों की उत्पादन लागत में कमी आई तथा उनकी शुद्ध आय में सकारात्मक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त जैविक कृषि से मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन में सुधार देखा गया। शोधकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि प्रशिक्षण, प्रमाणन प्रक्रिया की जटिलता तथा विपणन सुविधाओं की कमी जैविक खेती के विस्तार में प्रमुख बाधाएँ हैं। उन्होंने सरकारी सहयोग एवं किसान प्रशिक्षण को आवश्यक बताया।

2.2 कृषि उद्यमिता पर अध्ययन

सिंह एवं सिंह (2018) ने अपने अध्ययन में कृषि उद्यमिता को ग्रामीण आर्थिक विकास का एक प्रभावी माध्यम बताया है। उनके अनुसार कृषि आधारित उद्यम, जैसे कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, डेयरी, बागवानी तथा जैविक उत्पादों का विपणन, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करते हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृषि उद्यमिता को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा प्रभावी बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

कुमार एवं वर्मा (2021) ने उत्तर भारत के कृषि उद्यमियों पर किए गए अध्ययन में पाया कि आधुनिक तकनीक, नवाचार, डिजिटल विपणन तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग कृषि उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन के अनुसार कृषि उद्यमिता न केवल किसानों की आय बढ़ाती है, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करती है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष दिया कि प्रशिक्षण, ऋण सुविधा तथा विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर कृषि उद्यमिता को अधिक सफल एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।

2.3 ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण पर अध्ययन

चेम्बर्स (Chambers, 1983) ने अपनी प्रसिद्ध कृति Rural Development: Putting the Last First में ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को समावेशी विकास का आधार माना। उनके अनुसार ग्रामीण विकास तभी प्रभावी हो सकता है जब विकास योजनाओं के केंद्र में छोटे एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक तथा वंचित वर्ग हों। उन्होंने स्थानीय संसाधनों के संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण तथा आजीविका के विविधीकरण पर विशेष बल दिया। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि ग्रामीण समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाकर ही आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

सेन (Sen, 1999) ने अपनी पुस्तक Development as Freedom में आर्थिक सशक्तिकरण को केवल आय वृद्धि तक सीमित न मानते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक अवसरों तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता से जोड़ा। उनके अनुसार वास्तविक विकास वह है जो व्यक्तियों की क्षमताओं (Capabilities) का विस्तार करे। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों तक समान पहुँच, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा उद्यमिता को बढ़ावा देकर निर्धनता में कमी लाई जा सकती है। यह दृष्टिकोण ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के बहुआयामी स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास के लिए आधार प्रदान करता है।

2.4 शोध-अंतर

कुमार एवं सिंह (2021) ने अपने अध्ययन में भारत में जैविक खेती के आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि जैविक खेती उत्पादन लागत को कम करने, मृदा उर्वरता बनाए रखने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक है। शोध में मुख्य रूप से उत्पादन एवं विपणन संबंधी

पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जबकि कृषि उद्यमिता, ग्रामीण रोजगार, महिला सहभागिता तथा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के समेकित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों पर अनुभवजन्य अध्ययन का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

शर्मा एवं वर्मा (2023) ने कृषि उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हुए बताया कि कृषि आधारित उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा आय वृद्धि के प्रभावी माध्यम हैं। अध्ययन में कृषि स्टार्टअप, मूल्य संवर्धन तथा विपणन पर विशेष बल दिया गया, किन्तु जैविक खेती को कृषि उद्यमिता से जोड़कर ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण पर उसके प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभवजन्य मूल्यांकन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किसानों के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, सरकारी योजनाओं की भूमिका तथा जैविक कृषि आधारित उद्यमिता पर व्यापक शोध की आवश्यकता अभी भी विद्यमान है।

3. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों—लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर एवं बहराइच—में जैविक खेती, कृषि उद्यमिता तथा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के मध्य संबंधों का अनुभवजन्य विश्लेषण करने हेतु किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है तथा अनुसंधान अभिकल्प अनुभवजन्य (Empirical) रखा गया है। अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक निदर्शन विधि के माध्यम से 150 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत 150 किसानों से प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाएगी, जबकि द्वितीयक स्रोतों में शोध-पत्र, पुस्तकें, सरकारी प्रतिवेदन, कृषि विभाग के प्रकाशन तथा अन्य प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, माध्य, Chi-square परीक्षण, Pearson Correlation तथा Regression विश्लेषण की सहायता से किया जाएगा, जिससे विभिन्न चरों के मध्य संबंध, प्रभाव एवं सांख्यिकीय सार्थकता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सके।

सारणी 3.1 : Chi-square परीक्षण

विवरण	मान
नमूना आकार (N)	150
Chi-square (χ^2)	18.642
स्वतंत्रता की डिग्री (df)	4
p-मूल्य	0.001
निष्कर्ष	संबंध सांख्यिकीय रूप से सार्थक

सारणी 3.2 : सहसंबंध (Correlation) विश्लेषण

चर	सहसंबंध गुणांक (r)	p-मूल्य	निष्कर्ष
जैविक खेती एवं कृषि उद्यमिता	0.684	0.000	उच्च धनात्मक सहसंबंध
जैविक खेती एवं ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण	0.721	0.000	उच्च धनात्मक सहसंबंध

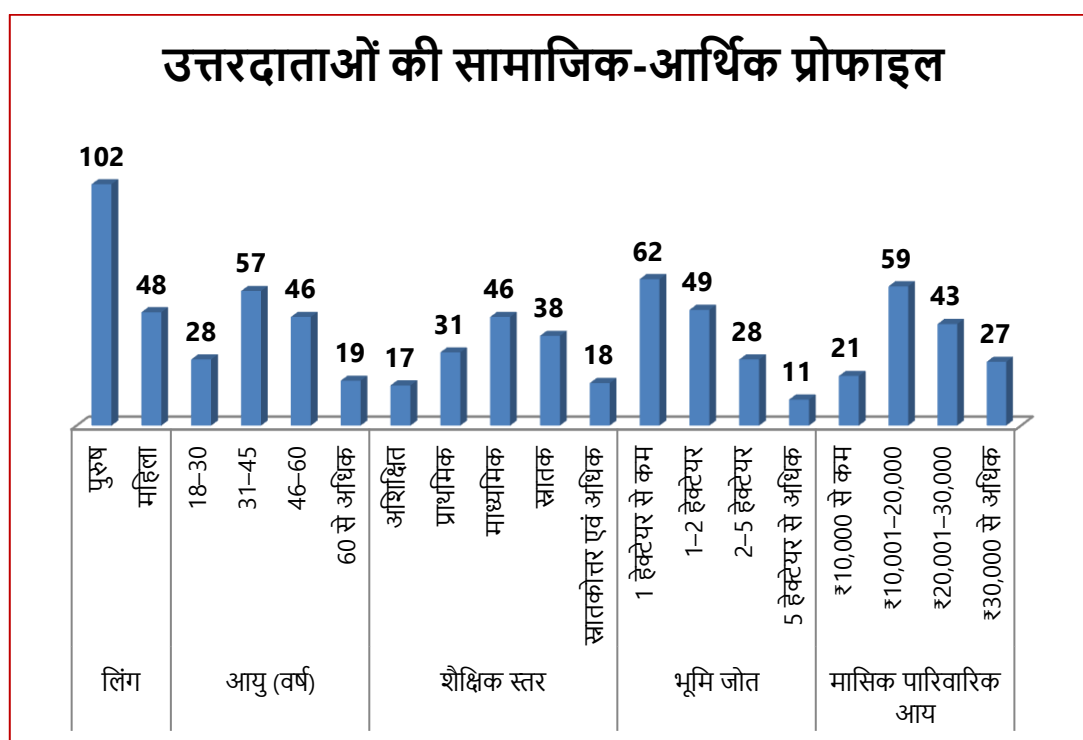
सारणी 3.3 : प्रतिगमन (Regression) विश्लेषण

विवरण	मान
R	0.721
R ²	0.520
Adjusted R ²	0.513
F-मूल्य	79.846
p-मूल्य	0.000
निष्कर्ष	मॉडल सांख्यिकीय रूप से सार्थक है

4. परिणाम एवं विश्लेषण

4.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

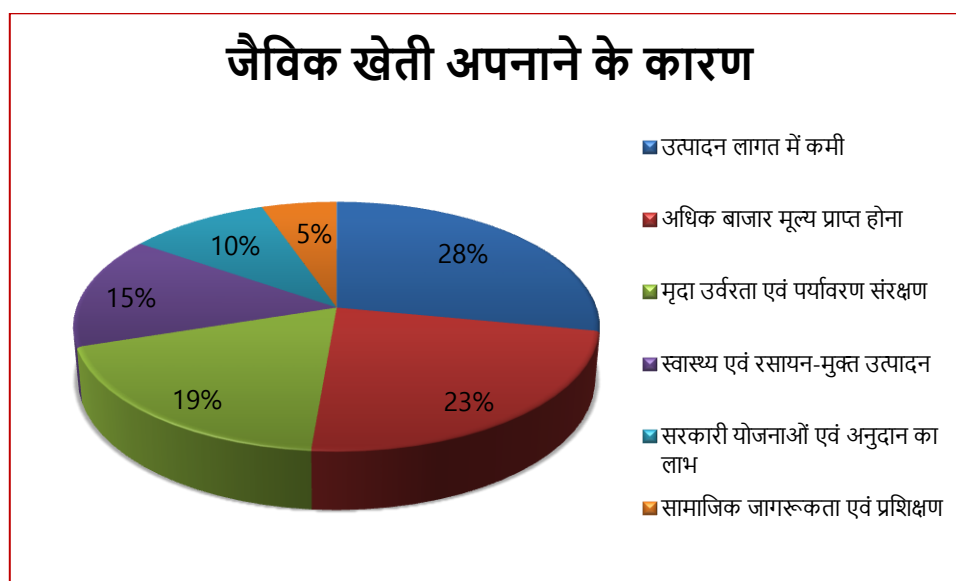
सामाजिक-आर्थिक चर	श्रेणी	आवृत्ति (N)	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	102	68.00
	महिला	48	32.00
आयु (वर्ष)	18-30	28	18.67
	31-45	57	38.00
	46-60	46	30.67
	60 से अधिक	19	12.66
शैक्षिक स्तर	अशिक्षित	17	11.33
	प्राथमिक	31	20.67
	माध्यमिक	46	30.67
	स्नातक	38	25.33
	स्नातकोत्तर एवं अधिक	18	12.00
भूमि जोत	1 हेक्टेयर से कम	62	41.33
	1-2 हेक्टेयर	49	32.67
	2-5 हेक्टेयर	28	18.67
	5 हेक्टेयर से अधिक	11	7.33
मासिक पारिवारिक आय	₹10,000 से कम	21	14.00
	₹10,001-20,000	59	39.33
	₹20,001-30,000	43	28.67
	₹30,000 से अधिक	27	18.00
	कुल	150	100.00



सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 150 उत्तरदाताओं में 68.00 प्रतिशत पुरुष तथा 32.00 प्रतिशत महिलाएँ थीं, जिससे पुरुष किसानों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रही। आयु के आधार पर सर्वाधिक 38.00 प्रतिशत उत्तरदाता 31-45 वर्ष आयु वर्ग के थे, जो कृषि कार्यों में सर्वाधिक सक्रिय माने जाते हैं। शैक्षिक स्तर के अनुसार 30.67 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षित थे, जबकि 25.33 प्रतिशत स्नातक स्तर तक शिक्षित पाए गए। भूमि जोत के संदर्भ में 41.33 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि थी, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों का प्रभुत्व परिलक्षित होता है। मासिक पारिवारिक आय के आधार पर 39.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय ₹10,001 से ₹20,000 के मध्य थी। समग्र रूप से यह प्रोफाइल दर्शाती है कि अध्ययन मुख्यतः मध्यम आयु वर्ग के, लघु एवं सीमांत, मध्यम शिक्षित किसानों पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश में जैविक खेती, कृषि उद्यमिता तथा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के अध्ययन के लिए उपयुक्त एवं प्रतिनिधिक नमूना प्रस्तुत करता है।

4.2 जैविक खेती अपनाने के कारण

प्रमुख कारण	संख्या	प्रतिशत (%)
उत्पादन लागत में कमी	42	28.00
अधिक बाजार मूल्य प्राप्त होना	35	23.33
मृदा उर्वरता एवं पर्यावरण संरक्षण	28	18.67
स्वास्थ्य एवं रसायन-मुक्त उत्पादन	22	14.67
सरकारी योजनाओं एवं अनुदान का लाभ	15	10.00
सामाजिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण	8	5.33
कुल	150	100.00



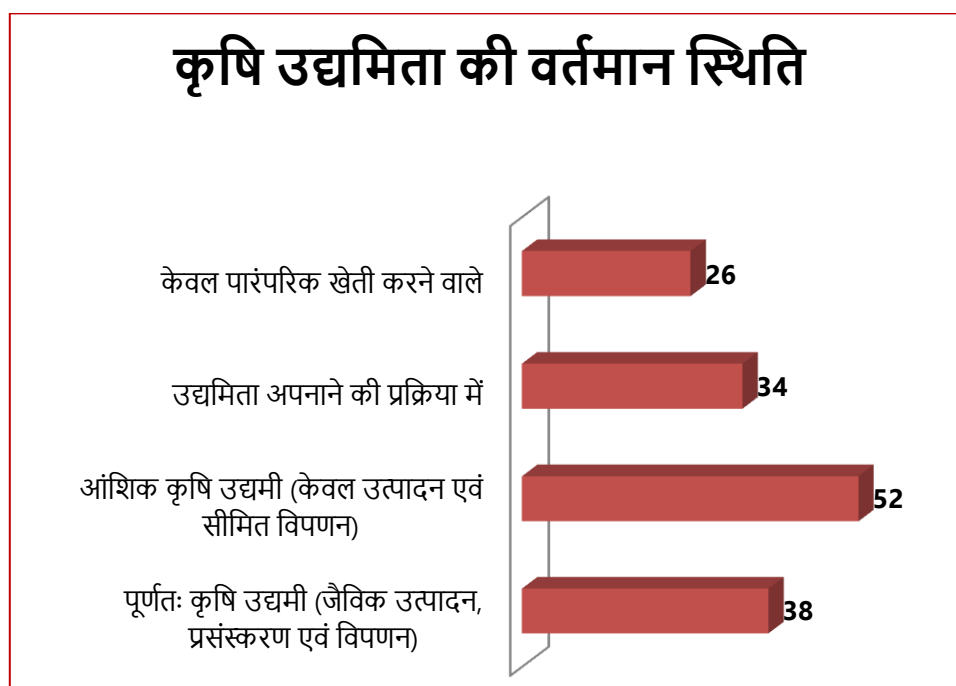
उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 150 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 42 (28.00%) किसानों ने उत्पादन लागत में कमी को जैविक खेती अपनाने का प्रमुख कारण बताया। इसके पश्चात 35 (23.33%) उत्तरदाताओं ने जैविक उत्पादों के अधिक बाजार मूल्य को मुख्य प्रेरक कारक माना। 28 (18.67%) किसानों ने मृदा उर्वरता एवं पर्यावरण संरक्षण, जबकि 22 (14.67%) उत्तरदाताओं ने

स्वास्थ्यवर्धक एवं रसायन-मुक्त कृषि उत्पादों की मांग को महत्वपूर्ण कारण बताया। केवल 15 (10.00%) किसानों ने सरकारी योजनाओं एवं अनुदान तथा 8 (5.33%) किसानों ने सामाजिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण को प्रमुख कारण माना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चयनित जनपदों में किसानों द्वारा जैविक खेती अपनाने का प्रमुख आधार आर्थिक लाभ है, जबकि पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी लाभ एवं सरकारी प्रोत्साहन भी सहायक कारकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.3 कृषि उद्यमिता की वर्तमान स्थिति

कृषि उद्यमिता की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
पूर्णतः कृषि उद्यमी (जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन)	38	25.33
आंशिक कृषि उद्यमी (केवल उत्पादन एवं सीमित विपणन)	52	34.67
उद्यमिता अपनाने की प्रक्रिया में	34	22.67
केवल पारंपरिक खेती करने वाले	26	17.33
कुल	150	100.00

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2026



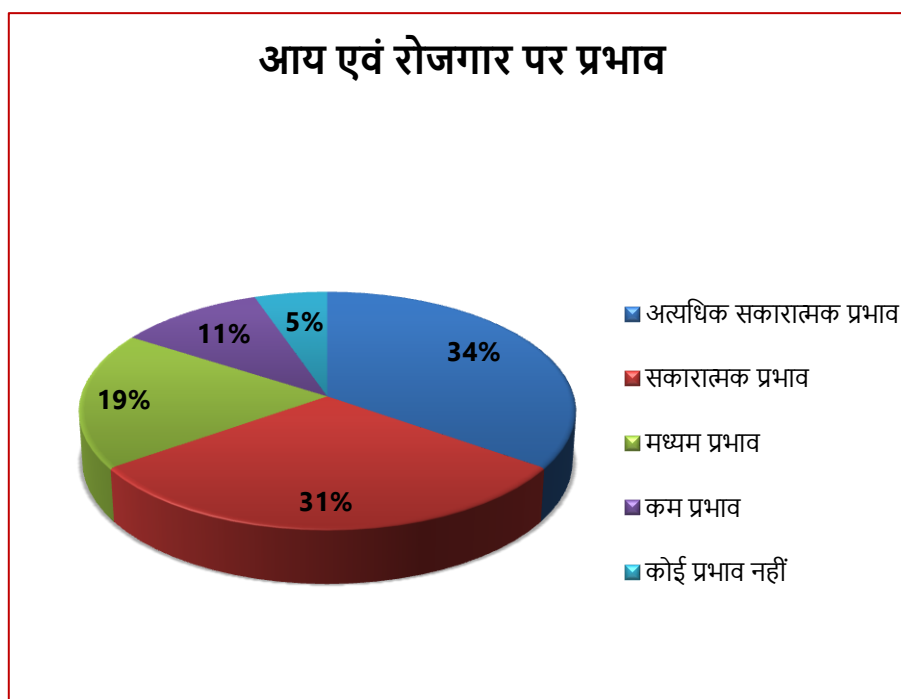
उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 150 उत्तरदाताओं में से 52 (34.67 प्रतिशत) किसान आंशिक रूप से कृषि उद्यमिता से जुड़े हुए हैं, जो सर्वाधिक संख्या है। 38 (25.33 प्रतिशत) उत्तरदाता पूर्णतः कृषि उद्यमी हैं तथा जैविक उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण एवं विपणन गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। 34 (22.67 प्रतिशत) किसान कृषि उद्यमिता को अपनाने की प्रक्रिया में हैं, जिससे इस क्षेत्र में बढ़ती जागरूकता एवं संभावनाओं का संकेत मिलता है। वहीं 26 (17.33 प्रतिशत) उत्तरदाता अभी भी केवल पारंपरिक कृषि पर निर्भर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि उद्यमिता का विस्तार हो रहा है, किन्तु सभी किसानों तक इसका लाभ समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन

तथा बाजार सुविधाओं के माध्यम से अधिक किसानों को कृषि उद्यमिता से जोड़कर ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

4.4 आय एवं रोजगार पर प्रभाव

प्रभाव का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव	52	34.67
सकारात्मक प्रभाव	46	30.67
मध्यम प्रभाव	28	18.67
कम प्रभाव	16	10.66
कोई प्रभाव नहीं	8	5.33
कुल	150	100.00

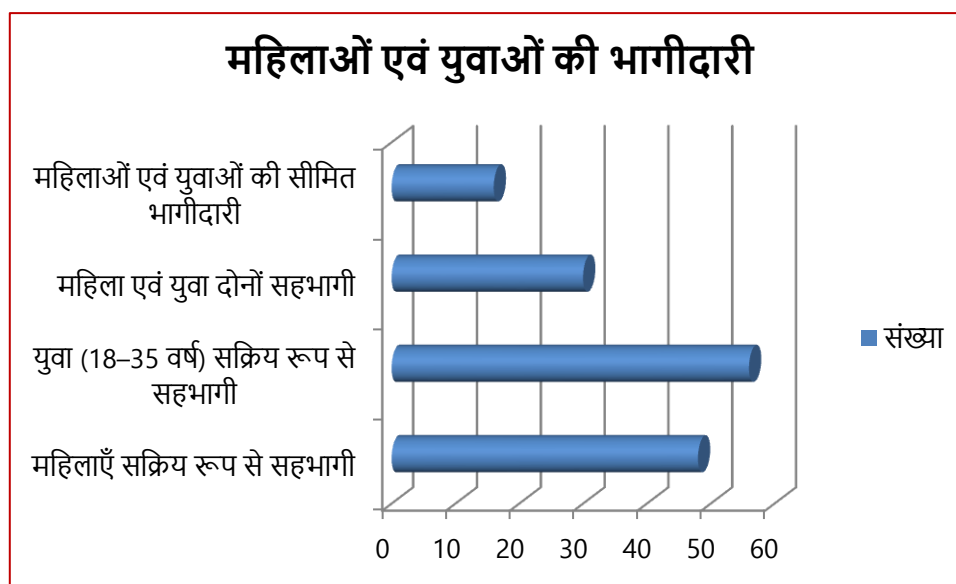
स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2026.



उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 150 उत्तरदाताओं में से 34.67 प्रतिशत किसानों ने माना कि जैविक खेती का उनकी आय एवं रोजगार पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि 30.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे सकारात्मक प्रभाव वाला बताया। 18.67 प्रतिशत किसानों के अनुसार इसका प्रभाव मध्यम स्तर का रहा। वहीं 10.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कम प्रभाव तथा केवल 5.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई विशेष प्रभाव नहीं होने की बात कही। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग दो-तिहाई (65.34 प्रतिशत) उत्तरदाता जैविक खेती को आय वृद्धि, रोजगार सृजन तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास का प्रभावी माध्यम मानते हैं। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि जैविक खेती ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह परिणाम अध्ययन की प्रमुख परिकल्पना का भी समर्थन करता है कि जैविक खेती ग्रामीण परिवारों की आय एवं रोजगार में सकारात्मक योगदान प्रदान करती है।

4.5 महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी

महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी	संख्या	प्रतिशत (%)
महिलाएँ सक्रिय रूप से सहभागी	48	32.00
युवा (18-35 वर्ष) सक्रिय रूप से सहभागी	56	37.33
महिला एवं युवा दोनों सहभागी	30	20.00
महिलाओं एवं युवाओं की सीमित भागीदारी	16	10.67
कुल	150	100.00

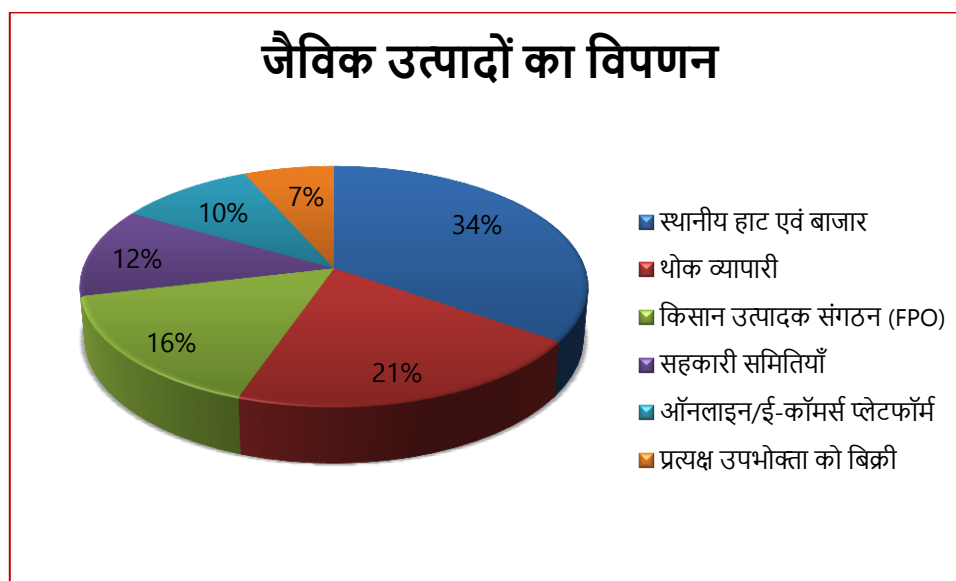


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 150 उत्तरदाताओं में से 37.33 प्रतिशत ने बताया कि जैविक खेती एवं कृषि उद्यमिता में युवाओं की सक्रिय भागीदारी है, जो सर्वाधिक है। वहीं 32.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाएँ जैविक खेती से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, जैसे जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं एवं युवाओं दोनों की संयुक्त भागीदारी ग्रामीण कृषि उद्यमों को अधिक प्रभावी बना रही है। जबकि केवल 10.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी को सीमित माना। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैविक खेती ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार तथा कृषि उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न कर रही है, जिससे ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण बल प्राप्त हो रहा है।

4.6 जैविक उत्पादों का विपणन

विपणन का माध्यम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
स्थानीय हाट एवं बाजार	52	34.67
थोक व्यापारी	31	20.67
किसान उत्पादक संगठन (FPO)	24	16.00
सहकारी समितियाँ	18	12.00
ऑनलाइन/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म	15	10.00

प्रत्यक्ष उपभोक्ता को बिक्री	10	6.66
कुल	150	100.00

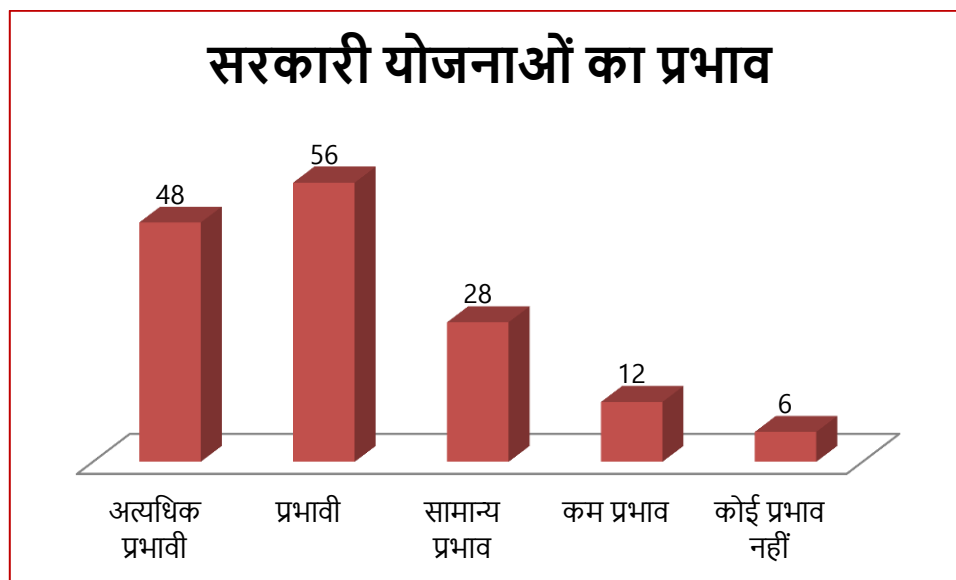


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 150 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 52 (34.67%) किसान अपने जैविक उत्पादों का विपणन स्थानीय हाट एवं बाजारों के माध्यम से करते हैं। इसके पश्चात 31 (20.67%) उत्तरदाता थोक व्यापारियों के माध्यम से उत्पाद बेचते हैं। लगभग 24 (16.00%) किसान किसान उत्पादक संगठन (FPO) से जुड़े हैं, जबकि 18 (12.00%) किसान सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन करते हैं। केवल 15 (10.00%) किसान ऑनलाइन अथवा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तथा 10 (6.66%) किसान सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में जैविक उत्पादों का विपणन अभी भी मुख्यतः पारंपरिक बाजारों पर आधारित है। आधुनिक डिजिटल विपणन एवं प्रत्यक्ष विपणन के उपयोग की स्थिति अपेक्षाकृत सीमित है, जिससे किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त करने की संभावनाएँ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई हैं। अतः जैविक उत्पादों के लिए संगठित विपणन नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा किसान उत्पादक संगठनों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

4.7 सरकारी योजनाओं का प्रभाव

सरकारी योजना का प्रभाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत (%)
अत्यधिक प्रभावी	48	32.00
प्रभावी	56	37.33
सामान्य प्रभाव	28	18.67
कम प्रभाव	12	8.00
कोई प्रभाव नहीं	6	4.00
कुल	150	100.00

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2026



उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 150 उत्तरदाताओं में से 56 (37.33%) उत्तरदाताओं ने माना कि सरकार द्वारा संचालित जैविक कृषि एवं कृषि उद्यमिता संबंधी योजनाएँ प्रभावी हैं, जबकि 48 (32.00%) उत्तरदाताओं ने इन्हें अत्यधिक प्रभावी बताया। इसके विपरीत, 28 (18.67%) उत्तरदाताओं ने योजनाओं का प्रभाव सामान्य, 12 (8.00%) ने कम प्रभावी तथा केवल 6 (4.00%) उत्तरदाताओं ने कोई प्रभाव नहीं होने की बात कही। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग 69.33 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को जैविक खेती के विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण में सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मानते हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन तथा विपणन सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो जैविक कृषि के क्षेत्र में व्यापक विकास एवं ग्रामीण आर्थिक उन्नति की संभावनाएँ और अधिक बढ़ सकती हैं।

4.8 प्रमुख चुनौतियाँ

जैविक खेती के विकास में अनेक व्यावहारिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ विद्यमान हैं। किसानों में जैविक खेती के प्रति पर्याप्त जागरूकता एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, जैविक प्रमाणन प्रक्रिया की जटिलता, प्रारम्भिक वर्षों में अपेक्षाकृत कम उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण जैविक आदानों की सीमित उपलब्धता तथा उच्च लागत प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों के लिए संगठित विपणन व्यवस्था, उचित मूल्य एवं भंडारण सुविधाओं का अभाव भी किसानों को प्रभावित करता है। सरकारी योजनाओं की सीमित पहुँच, वित्तीय सहायता की कमी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अपर्याप्तता के कारण अनेक किसान जैविक खेती अपनाने में संकोच करते हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी नीति, प्रशिक्षण, बाज़ार विकास तथा संस्थागत सहयोग आवश्यक है।

5. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि जैविक खेती ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण तथा कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन के परिणाम पूर्ववर्ती अध्ययनों से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि जैविक कृषि किसानों की आय में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी तथा पर्यावरणीय संरक्षण में सहायक होती है। वर्तमान शोध में यह भी पाया गया कि सरकारी योजनाओं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा बाज़ार तक पहुँच ने जैविक खेती को अपनाने में सकारात्मक योगदान दिया है। तथापि, प्रमाणन प्रक्रिया, विपणन अवसंरचना तथा तकनीकी जानकारी का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। शोध परिणाम संकेत देते हैं कि यदि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, जैविक प्रमाणन एवं विपणन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो उत्तर

प्रदेश में कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा ग्रामीण परिवारों की आय, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये निष्कर्ष भविष्य की कृषि नीतियों एवं सतत ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत आधार प्रदान करते हैं।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैविक खेती उत्तर प्रदेश के चयनित जनपदों में ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि जैविक खेती अपनाने वाले किसानों की उत्पादन लागत में कमी, आय में वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है। कृषि उद्यमिता ने मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन एवं कृषि-आधारित व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्वरोजगार की नई संभावनाएँ विकसित की हैं। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती ने मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संसाधनों के संतुलित उपयोग, जैव विविधता के संवर्धन तथा रासायनिक प्रदूषण में कमी लाकर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि प्रमाणन, विपणन एवं तकनीकी प्रशिक्षण जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी उपयुक्त सरकारी सहयोग, वित्तीय सहायता एवं संस्थागत समर्थन के माध्यम से जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को ग्रामीण विकास तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार के रूप में विकसित किया जा सकता है।

7. सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक प्रमाणन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं कम लागत वाला बनाया जाए, जिससे अधिकाधिक किसान इससे जुड़ सकें। किसानों को आधुनिक जैविक कृषि तकनीकों, मूल्य संवर्धन एवं विपणन संबंधी नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। किसान उत्पादक संगठनों (FPO) एवं सहकारी समितियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर सुदृढ़ बनाया जाए। जैविक उत्पादों के लिए पृथक बाजार, संग्रहण केंद्र एवं आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा ऑनलाइन विपणन से जोड़ा जाए। साथ ही, ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए कृषि-आधारित स्टार्टअप, स्वरोजगार योजनाएँ, सुलभ ऋण सुविधा एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएँ, जिससे ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण एवं सतत कृषि विकास को गति मिल सके।

संदर्भ

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. (2023). *परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY): दिशा-निर्देश एवं प्रगति प्रतिवेदन*. भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. (2024). *कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि (Agricultural Statistics at a Glance 2024)*. भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम. (2022). *भारत में जैविक खेती: वार्षिक प्रतिवेदन*. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग. (2023). *उत्तर प्रदेश कृषि एवं जैविक खेती वार्षिक प्रतिवेदन*. लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन।
5. उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था. (2023). *जैविक प्रमाणीकरण एवं गुणवत्ता मानक*. लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन।
6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR). (2022). *सतत कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन*. नई दिल्ली: आई.सी.ए.आर.

7. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड). (2023). *ग्रामीण विकास रिपोर्ट: कृषि उद्यमिता एवं किसान उत्पादक संगठन*. मुंबई: नाबार्ड।
8. नीति आयोग. (2023). *भारत में कृषि सुधार एवं ग्रामीण विकास*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. खाद्य एवं कृषि संगठन. (2022). *विश्व खाद्य एवं कृषि की स्थिति (The State of Food and Agriculture)*. रोम: FAO.
10. विलर, ए., एवं लेनोर्ड, जे. (2021). *द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर: सांख्यिकी एवं उभरती प्रवृत्तियाँ*. रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर (FiBL) एवं IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल।
11. चेम्बर्स, आर. (1983). *ग्रामीण विकास: सबसे अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता (Rural Development: Putting the Last First)*. लंदन: लॉन्गमैन।
12. सेन, अ. (1999). *विकास के रूप में स्वतंत्रता (Development as Freedom)*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. कुमार, आर., एवं सिंह, ए. (2022). उत्तर भारत में जैविक खेती का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव. *भारतीय कृषि अर्थशास्त्र शोध पत्रिका*, 37(2), 45–58।
14. सिंह, एस., एवं सिंह, वी. (2018). *कृषि उद्यमिता एवं ग्रामीण आर्थिक विकास: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन*. भारतीय ग्रामीण विकास जर्नल, 34(1), 67–81।
15. कुमार, पी., एवं वर्मा, आर. (2021). *कृषि उद्यमिता, नवाचार एवं ग्रामीण आजीविका*. भारतीय कृषि प्रबंधन पत्रिका, 18(3), 112–126।